



नई शुरुआत का वक्त

श्रीलंका में चीन की आलोचना करने वाले भी कम नहीं जो यह आरोप जड़ते हैं कि देश को कर्ज में डुबोने के लिए चीन जिम्मेदार है।

फ़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर श्रीलंका पोटुजना पेरमुना (एसएलपीपी) के उम्मीदवार गोताबाया राजपक्षे चुने गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे के भाई गोताबाया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे सजीथ प्रेमदासा को परास्त किया है। यानी इस बार चुनाव मैदान में उतरे दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार श्रीलंका की ताकतवर राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये नतीजे निश्चित ही श्रीलंका के भारत और चीन के साथ रिश्तों की नई रूपरेखा तय करने वाले होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी चुनावों में बढ़त मिलने के दौरान ही राजपक्षे को बधाई दी तो यही कहा कि वे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध गहरे करने और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा बढ़ाने के लिए साथ काम करने को उत्साहित हैं। श्रीलंका में इसी साल अप्रैल में ईस्टर पर बड़े आत्मघाती हमले के बाद हुए इन चुनावों पर सबकी नजर थी। हालांकि दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने-अपने तरीके से भारत के साथ अपने नजदीकी रिश्तों का प्रचार तो किया पर भारत कहीं मुद्दा नहीं बना। गोताबाया ने ईस्टर पर आत्मघाती हमले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ही बड़ा मुद्दा बनाया और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली।

दरअसल, श्रीलंका के बीच संबंधों को लेकर भारत की चिंता दूसरी है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश किया है। वर्ष 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में महिन्द्रा राजपक्षे की हार की बड़ी वजह यह निवेश और राजपक्षे की भारत से दूरियां रही थीं। यह बात और है कि महिन्द्रा राजपक्षे के कार्यकाल में बने श्रीलंका के हम्बन्टोटा बंदरगाह तक को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वजह साफ़ रही। यह बंदरगाह चीनी युद्धपोतों की आवाजाही के लिए हिन्द महासागर में ऐसी जगह पर है जहां से इन्हें तेल आपूर्ति की जा सकती है। कोलम्बो बंदरगाह को विकसित करने में भी चीन की भूमिका रही है। चीन के इन प्रयासों के इतर श्रीलंका ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में कम रुचि दिखाई है। यहां तक कि कोलम्बो बंदरगाह में ईस्टर्न कटेनर बनाने का श्रीलंका के साथ हुआ समझौता भी काफी देरी से हुआ। यह तो तब है जब भारत आने वाला काफी सामान कोलंबो बंदरगाह होकर आता है। श्रीलंका में चीन की आलोचना करने वाले भी कम नहीं जो यह आरोप जड़ते हैं कि देश को कर्ज में डुबोने के लिए चीन जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोताबाया अपने भाई की नीतियों को जारी रखेंगे या फिर भारत से संबंधों की नई शुरुआत करेंगे। वहां अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से तमिलों के प्रति भी राजपक्षे का क्या रवैया रहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी।



Quote of the day

अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। इन चुनावों में तो कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है।

संजय सिंह,
आम आदमी पार्टी

प्रसंगवश

हक से वंचित क्यों

हाल ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 में सामने आया है कि राजस्थान की जेलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन के बाद तैयार हुई इस रिपोर्ट में राजस्थान को राष्ट्र स्तर पर बारहवीं रैंक मिली है। इसका कारण यह है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा बंदी तो रखे ही जा रहे हैं, प्रत्येक कैदी पर व्यय की जाने वाली राशि भी अत्यंत कम है। उस पर स्टाफ और संसाधनों की लगातार कमी कोढ़ में खाज का ही काम कर रही है। दरअसल, वर्ष 2016-17 का आंकड़ा देखें तो राजस्थान में प्रति कैदी महज 14 हजार 683 रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बजट की भी 77 फीसदी राशि ही खर्च की गई। हालात ये हैं कि राज्य की जेलों में अधिकांशों, कांडर और कर्कशानल स्टाफ के स्वीकृत में से आधे पद रिक्त चल रहे हैं। यह स्थिति भी तब है, जब उच्च न्यायालय भी जेलों में क्षमता से ज्यादा बंदी रखने पर चिंता जाहिर कर चुका है। ऐसे में कैदियों को तो नारकीय जीवन जीने की विवश होना ही पड़ रहा है, जेलों की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल भी गहरा रहे हैं।

बेशक, किसी ने अपराध किया है तो न्यायालय से सुनाई गई सजा उसे भुगतनी ही होगी। लेकिन इसका अर्थ यह कदाई नहीं कि अपराधी होने के बाद वह मनुष्य नहीं रहा। मनुष्य ही नहीं, बल्कि कैदी होने के नाते भी उसके कुछ अधिकार हैं, जिनसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारों और सरकार को मानवीय आधार पर इस पर मंथन करना चाहिए। जेलों में नियमानुसार सुविधाएं-व्यवस्थाएं तय करनी चाहिए। अभी जेल स्टाफ में केवल 10.6 फीसदी महिलाएं हैं, इनकी संख्या बढ़ाने पर भी काम करना चाहिए। वहीं, 'सुविधा शुल्क' वसूलकर कैदियों को मोबाइल, मादक पदार्थ आदि उपलब्ध कराने के मामले आए दिन सामने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की कई जेलों में ऐसी वसूली का खुलासा हुआ है। सरकार को इस पर भी लगातार कसनी चाहिए।

हमसे ऐसे जुड़ें

प्रकाशित सामग्री पर आपकी राय व विषय वकत के सुझाव हमें भेजें

@PatrikaNews | edit@epatrika.com

समानता की विचारधारा हो

महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासत ज़ोरों पर है। जोड़-तोड़ व गलबधन की नई विचारधाराएं एक-दूसरे से जुड़ रही हैं। आज मानवता व इंसाफियत का तकाजा है कि हम सभी समानता की विचारधारा को बढ़ावा दें। किसी एक कट्टर विचारधारा का अनुसरण करने की एकता व अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है, वैमनस्यता बढ़ा सकता है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है।

— हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

शिक्षकों की उपस्थिति अहम

पाठशाला में समय पर तथा नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति से ही गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य और विद्यालय की सक्रियता को सुनिश्चित किया जा सकता है। नियमितता के साथ-साथ पूरा समय यदि शिक्षक स्वेच्छा से विद्यालय में दें तो ई-अटेंडेंस का गिरोध स्वतः समाप्त होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में देश की गणना अग्रिम क्रम पर ले जाने के लिए और नियमित उपस्थिति के लिए शिक्षक यदि स्वेच्छा से काम लें, तो बेहतर होगा।

— बी.एल. शर्मा, इ-मेल

सांकेतिक हो आवेदन शुल्क

लंबे इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य चर सेवा परीक्षा विज्ञापन जारी किया जिससे इस परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली। लेकिन आवेदन शुल्क में बेतहाशा वृद्धि ने उम्मीदवारों को निराश किया है। एक और राज्य सरकारें सरकारी योजनाओं के जरिए वंचित वर्ग को आर्थिक मदद दे रही हैं, तो दूसरी और भारी भ्रकम आवेदन शुल्क वसूल रही है। परीक्षा फ्री सांकेतिक होनी चाहिए।

— सत्य प्रकाश, समस्तीपुर

जहां तक टेलिकॉम सेक्टर के रिवाइवल की बात है, तो कुछ बड़ा करने की जरूरत है। पहला कदम यह हो कि सरकार पॉलिसी निर्धारण में स्थिरता लाए। टेलिकॉम पॉलिसी व्यापक बनाने की जरूरत है। अक्सर यह बात भी उठती है कि 'लेवल प्लेइंग फील्ड' नहीं है।

ढह गया ताश के पत्तों का महल!

अनुराग भारद्वाज



विभिन्न टेलिकॉम कंपनियों में अहम पदों पर रहे। सेक्टर की बारीकियों के जानकार। फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग और स्वतंत्र लेखन में सक्रिय।

2011 में सरकार नई टेलिकॉम पॉलिसी ले आई। पहले व्यवस्था थी कि कंपनी निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस खरीदकर सेवाएं दे सकती थी। नई पॉलिसी के तहत लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को अलग कर दिया गया। व्यवस्था की गई कि लाइसेंस खत्म होने पर स्पेक्ट्रम भी कंपनी से सरकार को चला जाएगा। कंपनी को अगर दुबारा सेवा शुरू करनी है तो दोनों के लिए अलग भुगतान करना होगा और किसी अन्य ऑपरेटर की तरह नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा।

अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। इन चुनावों में तो कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है।

संजय सिंह,
आम आदमी पार्टी

प्रसंगवश

हक से वंचित क्यों

हाल ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 में सामने आया है कि राजस्थान की जेलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन के बाद तैयार हुई इस रिपोर्ट में राजस्थान को राष्ट्र स्तर पर बारहवीं रैंक मिली है। इसका कारण यह है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा बंदी तो रखे ही जा रहे हैं, प्रत्येक कैदी पर व्यय की जाने वाली राशि भी अत्यंत कम है। उस पर स्टाफ और संसाधनों की लगातार कमी कोढ़ में खाज का ही काम कर रही है। दरअसल, वर्ष 2016-17 का आंकड़ा देखें तो राजस्थान में प्रति कैदी महज 14 हजार 683 रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बजट की भी 77 फीसदी राशि ही खर्च की गई। हालात ये हैं कि राज्य की जेलों में अधिकांशों, कांडर और कर्कशानल स्टाफ के स्वीकृत में से आधे पद रिक्त चल रहे हैं। यह स्थिति भी तब है, जब उच्च न्यायालय भी जेलों में क्षमता से ज्यादा बंदी रखने पर चिंता जाहिर कर चुका है। ऐसे में कैदियों को तो नारकीय जीवन जीने की विवश होना ही पड़ रहा है, जेलों की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल भी गहरा रहे हैं।

बेशक, किसी ने अपराध किया है तो न्यायालय से सुनाई गई सजा उसे भुगतनी ही होगी। लेकिन इसका अर्थ यह कदाई नहीं कि अपराधी होने के बाद वह मनुष्य नहीं रहा। मनुष्य ही नहीं, बल्कि कैदी होने के नाते भी उसके कुछ अधिकार हैं, जिनसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारों और सरकार को मानवीय आधार पर इस पर मंथन करना चाहिए। जेलों में नियमानुसार सुविधाएं-व्यवस्थाएं तय करनी चाहिए। अभी जेल स्टाफ में केवल 10.6 फीसदी महिलाएं हैं, इनकी संख्या बढ़ाने पर भी काम करना चाहिए। वहीं, 'सुविधा शुल्क' वसूलकर कैदियों को मोबाइल, मादक पदार्थ आदि उपलब्ध कराने के मामले आए दिन सामने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की कई जेलों में ऐसी वसूली का खुलासा हुआ है। सरकार को इस पर भी लगातार कसनी चाहिए।

हमसे ऐसे जुड़ें

प्रकाशित सामग्री पर आपकी राय व विषय वकत के सुझाव हमें भेजें

@PatrikaNews | edit@epatrika.com

समानता की विचारधारा हो

महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासत ज़ोरों पर है। जोड़-तोड़ व गलबधन की नई विचारधाराएं एक-दूसरे से जुड़ रही हैं। आज मानवता व इंसाफियत का तकाजा है कि हम सभी समानता की विचारधारा को बढ़ावा दें। किसी एक कट्टर विचारधारा का अनुसरण करने की एकता व अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है, वैमनस्यता बढ़ा सकता है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है।

— हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

समानता की विचारधारा हो

महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासत ज़ोरों पर है। जोड़-तोड़ व गलबधन की नई विचारधाराएं एक-दूसरे से जुड़ रही हैं। आज मानवता व इंसाफियत का तकाजा है कि हम सभी समानता की विचारधारा को बढ़ावा दें। किसी एक कट्टर विचारधारा का अनुसरण करने की एकता व अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है, वैमनस्यता बढ़ा सकता है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है।

— हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

शिक्षकों की उपस्थिति अहम

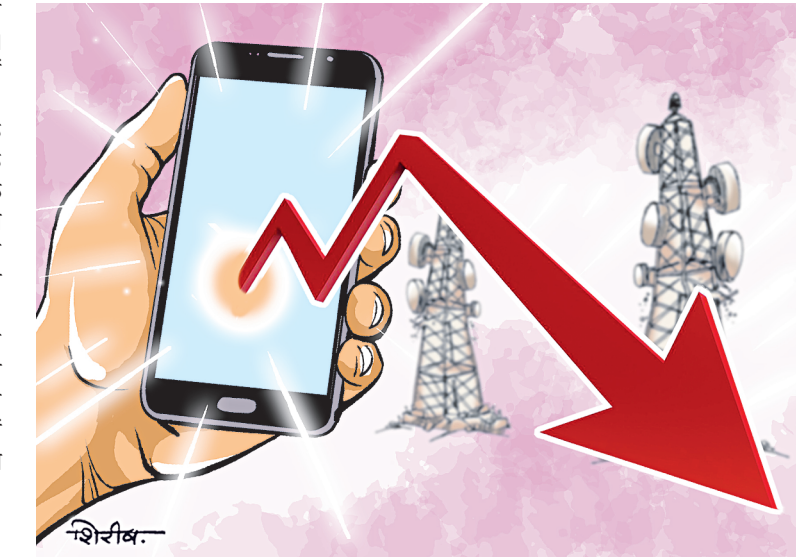
पाठशाला में समय पर तथा नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति से ही गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य और विद्यालय की सक्रियता को सुनिश्चित किया जा सकता है। नियमितता के साथ-साथ पूरा समय यदि शिक्षक स्वेच्छा से विद्यालय में दें तो ई-अटेंडेंस का गिरोध स्वतः समाप्त होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में देश की गणना अग्रिम क्रम पर ले जाने के लिए और नियमित उपस्थिति के लिए शिक्षक यदि स्वेच्छा से काम लें, तो बेहतर होगा।

— बी.एल. शर्मा, इ-मेल

सांकेतिक हो आवेदन शुल्क

लंबे इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य चर सेवा परीक्षा विज्ञापन जारी किया जिससे इस परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली। लेकिन आवेदन शुल्क में बेतहाशा वृद्धि ने उम्मीदवारों को निराश किया है। एक और राज्य सरकारें सरकारी योजनाओं के जरिए वंचित वर्ग को आर्थिक मदद दे रही हैं, तो दूसरी और भारी भ्रकम आवेदन शुल्क वसूल रही है। परीक्षा फ्री सांकेतिक होनी चाहिए।

— सत्य प्रकाश, समस्तीपुर



टेलिकॉम सेक्टर में डोमिनो प्रभाव की शुरुआत 10 जनवरी 2008 को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर हुई थी, जब स्पेक्ट्रम नीलामी की निविदाओं के लिए चंद घंटों की मोहलत दी गई थी।

टेलीसर्विसेज और एयरसेल ने कुल मिलाकर 50,628 करोड़ रुपए देकर अपने कई सर्किलों में 3जी सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस लिया। स्पेक्ट्रम खरीदने के अलावा, 3जी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी पैसा लगा। टेलिकॉम को 'सनराइज' सेक्टर मानते हुए बैंकों ने कंपनियों को लोन देने में कोताही नहीं बरती। देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में 'इंडियन टेलिकॉम एक्ससेस स्टोरी' का प्रचार कर सरकारें उदारवाद का ढोल पीटती रहीं। तभी कंपनियों को प्राप्त होने वाला 'एक्सेज रेवेन्यू पर यूजर' (प्रति व्यक्ति राजस्व) यानी आरपू भी घटने लगा था। हर विशेषज्ञ 'लॉन्ग टर्म बेनेफिट' की बात कहकर अब भी आशान्वित थे। वही, छोटी कंपनियों का दम घुटने लगा और तब यह कहा जाने लगा कि टेलिकॉम में 'कंसोलिडेशन' (समेकन) से हालात सुधर जाएंगे। 3जी सेवाओं का मुकम्मल तौर पर शुरू न हो पाना कोढ़ में खाज का काम कर गया। लिहाजा, कंपनियों का जहां ग्रांस रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, ज्यादा खर्चों और एसेट यूटिलाइजेशन में कमी की वजह से शुद्ध मुनाफा गिरने लगा और बैलेंसशीट्स बिगड़ने लगीं। 2011 में सरकार नई टेलिकॉम पॉलिसी ले आई। पहले व्यवस्था थी कि कंपनी निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस खरीदकर सेवाएं दे सकती थी। नई पॉलिसी के तहत लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को अलग कर दिया गया। व्यवस्था की गई कि लाइसेंस खत्म होने पर स्पेक्ट्रम भी कंपनी से सरकार को चला जाएगा। कंपनी को अगर दुबारा

अपने साधकों की साधना और निष्ठा से ही संवरती है भाषा

भारतीय जीवन मूल्यों का मूल है संस्कृत



संस्कृत विभाग में मुस्लिम अभ्यर्थी के चयन के विरोध में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर रुद्राभिषेक भी किया।

भाषाएं कभी भी संकीर्णता स्वीकार नहीं करती क्योंकि वे नदियों की तरह होती हैं। उनके प्रवाह को रोकने का प्रयास उनकी प्रांजलता के बोध को धर्मसंकट में डाल देता है।

हिन्दू न्योछावर किए जा सकते हैं। कृष्ण के प्रेम में 'मानुष हों तो वही रसखान, बसें बूज गोकुल गांव के ग्वारन' जैसे मनोहर छंद लिखने वाले रसखान के उल्लेख बिना क्या कृष्ण काव्य की चर्चा पूरी हो सकती है? ठीक इसी तरह से अब्दुर्हीम खानखाना के नाम के बिना संस्कृत साधकों की चर्चा अधूरी ही रहेगी। खानखाना ही क्यों, अलबरूनी और अमीर खुसरो के बारे में भी माना जाता है कि वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। दरअसल, सातवीं शताब्दी में जब अरब में खलीफा वंश का शासन था तब यहिया बिन खालिद बसमकी ने

इसीलिए 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे भारतीयों के जीवन को समझने के लिए संस्कृत सीखें। इसी का परिणाम यह हुआ कि आज चार्ल्स बिल्किंस द्वारा किया गया श्रीमद्भागवत और हितोपदेश का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। हेस्टिंग्स के निर्देशों के भी पहले हेनरिथ राय ने आगरा आकर मिशनरी कार्यों के लिए संस्कृत का अध्ययन किया था। विलियम जोंस, एक्वेरिल डू पेरोन, आगस्त विलहेम, फ्रेडरिक श्लेगल, विल्हेम हम्बोल्ट, आर्थर शॉपेन हाँवर, विलियम जॉस, मैक्समुलर जैसे कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का गूढ़ अध्ययन किया और पश्चिमी देशों को भारत के आध्यात्मिक-सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराया।

संस्कृत की वैश्विक लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज यूरोप, अमेरिका, इजरायल और जर्मनी सहित दुनिया के दो सौ विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। खाड़ी देशों में तो संस्कृत जानने वाले लोगों की मांग लगातार बढ़ने की खबर भी पिछले दिनों प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक प्राचीन दरगाह के मुतवल्ली पं. गुलाम दस्तगीर बिराजदार तो स्वयं को

'संस्कृत का गुलाम' कहते रहे। मुस्लिम मतानुबंजी होने के बावजूद उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी के निर्माणपत्र संस्कृत में छपवाए। उत्तरप्रदेश के कोशाम्बी जिले के छीता हरायपुर के रहने वाले पं. हयातुल्ला को तो वेदों के उनके ज्ञान के कारण 1967 में इलाहाबाद के एक संस्कृत समारोह में देशभर से आए संस्कृत विद्वानों के बीच चतुर्वेदी की उपाधि दी गई। वाराणसी की नाहिद आबिदी को संस्कृत में की गई साहित्य सेवा के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बदायूं के इसहाक तबीब पेशे से चिकित्सक हैं लेकिन बच्चों को शौकिया तौर पर संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने बाल साहित्य की 141 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें एक दर्जन से अधिक संस्कृत भाषा में हैं। इनके अलावा भी ऐसे कई मुस्लिम विद्वान हैं, जिनकी साधना की चर्चा किए बिना संस्कृत के सम्मकालीन संसार की बात पूरी नहीं हो सकेगी। जिस तरह से उर्दू ने रघुपति सहाय गोरखपुरी से लेकर शायरों का एक पूरी फेहरिस्त को सम्मान दिया है, ठीक उसी तरह से संस्कृत भी मुस्लिम विद्वानों की साधना पर गर्व करती है। आखिर भाषा तो अपने साधकों की साधना और निष्ठा से संवरती है, उसका किसी जातीय या धार्मिक पूर्वाग्रह से क्या संस्कार?

— अली खान, जैसलमेर

मेहमान परिंदों की सुरक्षा

विश्वविख्यात सांभर झील में पिछले कई दिनों से सेकड़ों पक्षियों की मौत की घटना बेहद दुःखद है। हजारों पक्षियों का आमाम-प्रवास व प्रवास स्थल सांभर झील में मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, पर परिंदों की सुरक्षा तय करने हेतु कोई कोशिश की जा रही हो, ऐसा नजर नहीं आता। इनकी सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की सतर्कता, चिकित्सकीय सहायता के अतिरिक्त रेस्क्यू सेंटर खोलकर स्थायी इंतजाम किए जा सकते हैं।

— अली खान, जैसलमेर

अवैध बजरी खनन से दोहरी मार

सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी खनन पर रोक लगाए दो वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन बजरी खनन का सिलसिला थमा नहीं। न तो सरकारी निर्माण कार्य रुके हैं और न ही निजी। इससे आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है व सरकार को भी रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। सरकार को ठेकेदारों को छोटी लीज जारी करनी चाहिए ताकि सरकार को भी रॉयल्टी का नुकसान न हो, जनता पर भी महंगाई की मार न पड़े।

— कमलेश कुमार स्वर्णकार, इ-मेल

प्रदूषण पर भी राजनीति

दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से प्रदूषण का बढ़ता स्तर जहां चिंता का प्रमुख विषय होना चाहिए, वहीं जनप्रतिनिधियों की ओर से इसे लेकर उदासीनता बरती जा रही है। वायु प्रदूषण का इतना भयावह स्तर और इस पर लगातार होती राजनीति वाकई हैरान कर देने वाली है। इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में मंथन करना तो दूर, कोई सोचने को भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है।

— इमरान अहमद, अजमेर